मुख्यमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान

का

गणतंत्र दिवस संदेश

भोपाल 26 जनवरी 2008

भाइयो और बहनो,

भारत के 58 वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं। आज हम स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को भी नमन करते हैं जिन्होंने प्रजातंत्र की स्थापना के लिये महान त्याग और बलिदान दिया।

आज के इस हर्ष और उल्लास के अवसर पर हमारे प्रदेश के नागरिक इस तथ्य पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि उनके द्वारा निर्वाचित राज्य सरकार अपने वायदों को पूरा करने के सतत् प्रयासों के साथ विकास के कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा निजी भागीदारी से वित्तीय संसाधन जुटाने में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है।

सड़क, बिजली, पानी सहित अधोसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, मजदूर एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिये अभिनव योजनाएं लागू की गई हैं।

प्रदेश की महिलाओं को सम्मान और बराबरी का हक़ सुनिश्चित करने के लिये उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ स्थानीय संस्थाओं और पंचायतों में पचास प्रतिशत, शिक्षकों के चयन में पचास प्रतिशत तथा पुलिस बल में दस प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वन समितियों के अध्यक्ष के एक तिहाई पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं। रानी दुर्गावती महिला पुलिस बटालियन का भी गठन किया जा रहा है। विकास योजनाओं का लाभ महिलाओं को सुनिश्चित करने के लिये 13 विभागों की योजनाओं में जेंडर बजटिंग लागू की गई है। महिला सशक्तिकरण तथा शिक्षा विस्तार के लिये लाड़ली लक्ष्मी, गांव की बेटी तथा मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी अभिनव योजनाएं शुरु की गई हैं। शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शालेय विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें, पाठ्य-पुस्तकें, गणवेश एवं छात्रवृत्ति-शिष्यवृत्ति देने की योजनाओं का विस्तार किया गया है।

पिछले चार वर्षों में 4117 करोड़ रुपये की लागत से 16300 किलोमीटर राज्य मार्ग एवं मुख्य सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 1600 करोड़ रुपये की लागत से 1800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण आगामी सितम्बर से शुरू हो जाएगा। इसी वर्ष 6771 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के लिये 479 करोड़ रुपये की विशेष योजना मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक 15892 किलोमीटर लंबाई की 3462 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इससे 4286 गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। अब तक इस वर्ष 2060 किलोमीटर लंबाई की 446 सड़कों को पूरा कर 590 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है।

विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिये राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। एक हजार मेगावाट क्षमता की

इंदिरासागर परियोजना तथा 520 मेगावाट की ओंकारेश्वर परियोजना समय से पहले पूरी करने के बाद इस वर्ष बीरसिंहपुर ताप विद्युत गृह में 500 मेगावाट तथा मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह में 20 मेगावाट की विद्युत इकाईयां क्रियाशील की गई हैं। इसके अलावा 425 मेगावाट की बाणसागर जल विद्युत योजना का निर्माण भी पूरा किया गया है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह में 210 मेगावाट की इकाई का काम इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। एक हजार मेगावाट क्षमता के मालवा ताप विद्युत गृह, 500 मेगावाट की सारणी ताप विस्तार इकाई तथा 1500 मेगावाट क्षमता की शहपुरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिये अग्रिम कारवाई भी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त विद्युत मांग की आपूर्ति के लिये 600 करोड़ रुपये की विद्युत क्रय हेतु प्रावधान किया गया है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के लिये नए विद्युत केन्द्र स्थापित करने तथा नई लाईनों को बिछाने का काम जारी है। किसानों को विद्युत दर में रियायत, अस्थायी कनेक्शन तथा लंबित देयकों के भुगतान के लिये सुविधाएं दी गई हैं।

राज्य में अपूर्ण और निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जा रहा है तथा प्रत्येक जिले के लिये नई लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मान, जोबट, बाणसागर तथा राजघाट जैसी वर्षों से लंबित परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इन प्रयासों से राज्य में सिंचाई तथा नर्मदा घाटी विकास विभागों द्वारा साढ़े चार लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। देश की पहली नदी जोड़ो केन-बेतवा परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा तैयार किया जा रहा है।

जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत प्रदेश में लगभग तीन लाख 60 हजार जल संरचनाओं का निर्माण उल्लेखनीय उपलब्धि है।

प्रत्येक गांव में जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति नागरिकों को जागरूक बनाया जा रहा है। खेत तालाब योजना तथा बलराम ताल योजना के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। हरियाली महोत्सव के अन्तर्गत दस करोड़ पौधे लगाये गये हैं।

खेती पर आज भी प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी की आजीविका निर्भर है। इस उद्देश्य से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अल्प अवधि के सहकारी ऋणों पर सात प्रतिशत ब्याज दर लागू की गई है। सहकारी समितियों के शत्-प्रतिशत किसान सदस्यों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत तीस लाख कार्ड दिये जा चुके हैं। प्राकृतिक आपदा में राहत देने संबंधी नियमों में संशोधन कर किसानों को पहले के मुकाबले दुगुनी राहत का प्रावधान किया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के नियमों को भी किसानों के हित में उदार बनाया गया है। खेती से संबंधित पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन जैसे व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गो-संवर्धन बोर्ड द्वारा जैविक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये किसानों में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

खेतिहर मजदूरों के सम्पूर्ण परिवार के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना लागू की गई है इस योजना के अन्तर्गत बच्चे के जन्म पर माता को 45 दिन एवं पिता को 15 दिन की मजदूरी के बराबर की राशि दी जाती है। उनके बच्चों की शिक्षा के लिये पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति, कन्या विवाह तथा परिवार के स्वास्थ्य एवं बीमा का भी प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों के लिये भी कर्मकार मण्डल द्वारा समान कल्याणकारी योजनाओं पर अमल किया जा रहा है।

राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में गंभीर कुपोषण की दर घटकर 0.78 प्रतिशत रह गई है। पोषण आहार के लिये बजट आवंटन 110 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आंगनवाड़ियों में गर्भवती माताओं और बच्चों के लिये सुविधाओं में विस्तार किया गया है तथा नये कार्यक्रम शुरु किये गये। मातृ एवं बाल मृत्यु दर घटाने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गर्भवती माताओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसव के लिये आर्थिक सहायता तथा अस्पताल तक परिवहन की योजनाओं से लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं।

प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के भवन स्वीकृत किये जा चुके हैं। इस वर्ष दस हजार से अधिक शिक्षकों के पद निर्मित किये गये हैं। 1119 माध्यमिक स्कूल, 737 हाई स्कूल तथा 185 हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। शालेय शिक्षा की परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु पांचवीं एवं आठवीं में बोर्ड की परीक्षा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। सागर में अगले सत्र से चिकित्सा महाविद्यालय की शुरुआत के लिये 150 करोड़ रुपये स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 45 साल बाद प्रदेश में कोई शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खुल रहा है। इससे बुंदेलखंड और विशेषकर सागर अंचल की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। रीवा में पशुचिकित्सा महाविद्यालय तथा गंजबासौदा में कृषि महाविद्यालय खोला गया है।

योजना के अन्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के विकास के लिये पिछले वर्ष के 1858 करोड़ रुपये के प्रावधान को इस वर्ष बढ़ाकर 2746 करोड़ रुपये किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के 1373 करोड़ रुपये के

प्रावधान को बढ़ाकर इस वर्ष 1833 करोड़ रुपये किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

मध्यप्रदेश को लगातार चार वर्षों से कुशल वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने का गौरव प्राप्त है। इस उपलब्धि के लिये राज्य को भारत सरकार से पिछले तीन वर्षों में 917 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। शिक्षा कर्मियों, संविदा शिक्षकों, पंचायत कर्मियों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाशर्तें और मानदेय-वेतन में सुधार, ब्रह्मस्वरूप समिति की सिफारिशों को लागू करना, शासकीय कर्मियों के मूल वेतन में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ना तथा उन्हें लगातार महंगाई भत्ते की किश्तों की स्वीकृति बेहतर वित्तीय स्थिति के कारण ही संभव हो सकी है।

राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों को कायम रखते हुए औद्योगिक विकास के लिये तेजी से आगे कदम बढ़ाये हैं। औद्योगीकरण में तेजी लाने के लिये खजुराहो में इन्वेस्टर्स मीट तथा सिंगापुर, मलेशिया, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ दिल्ली, मुम्बई और बंगलौर में निवेशकों से चर्चाओं के बाद इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता एक बड़ी उपलब्धि है। इससे प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए अच्छा वातावरण बना है।

सुराज मिशन के तहत प्रशासन को और अधिक जनोन्मुखी तथा संवेदनशील बनाने के प्रयासों में भी राज्य सरकार को काफी सफलता मिली है। ''मंथन'' कार्यशाला, मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन, जनदर्शन, मुख्यमंत्री निवास में पंचायतों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद के बाद समस्याओं का निराकरण तथा नये कार्यक्रमों की शुरूआत, जिला कार्यालयों में ''समाधान एक दिन में'' योजना, विकासखंड स्तर पर लोक कल्याण शिविरों का

आयोजन जैसे अभिनव कार्यक्रमों से प्रशासन जनता के अधिक निकट पहुंचा है जिससे समस्याओं के निराकरण में तेजी आयी है। रिक्त आरक्षित पदों पर भर्ती के साथ सामान्य वर्गों की भर्ती पर प्रतिबंध हटा लिया गया है।

जनसमस्याओं के निराकरण, पारदर्शिता बढ़ाने तथा तेजी से विकास के प्रयासों को बल प्रदान करने के लिये प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राजधानी को सभी विकासखंड मुख्यालयों से जोड़ने के लिये स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की योजना स्वीकृत हो चुकी है। इससे 9000 से अधिक कामन सर्विस सेंटरों की स्थापना की जायेगी।

खेल क्षेत्र में अनेक नई योजनाएं लागू की गई हैं। पुरुष और महिला हॉकी अकादमियों के गठन के साथ ही खेल बजट में लगभग पांच गुना वृद्धि की गई। विभिन्न खेलों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश के निवासियों को देश के बाहर स्थित आस्था केंद्रों की यात्रा के लिये अनुदान की सुविधा शुरू की गई है। राज्य सरकार ने जनभावनाओं का आदर करते हुए पाकिस्तान स्थित सिख तीर्थ स्थल ननकाना साहेब, हिन्दू तीर्थ स्थल माता हिंगलाज देवी मंदिर और तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिये 50 प्रतिशत व्यय देने की व्यवस्था की है।

प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा किये जाने वाले सम्मान अब बढ़ी हुई राशि के साथ दिये जा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर 6000 रुपये की गई है। जन भावनाओं का आदर करते हुए रामपथ विकास योजना पर भी काम शुरू हुआ है। नर्मदा परिक्रमा पथ का भी विकास किया जायेगा।

प्रदेश में सांस्कृतिक-धार्मिक केन्द्रों, ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक रमणीय केन्द्रों तथा औद्योगिक केन्द्रों में पर्यटन की असीम सभावनाएं हैं। ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटन केन्द्रों और होटल के स्वरूप में विकसित करने की पहल की जा रही है। पर्यटन के विकास में निजी पूंजी निवेश बढ़ाने के प्रयास शुरु किये गये हैं।

मध्यप्रदेश अन्य राज्यों के मुकाबले शांत प्रदेश है। परंतु अनेकों वर्षों से डकैती तथा पिछले कई वर्षों से नक्सलियों की गतिविधियां प्रदेश के कुछ हिस्सों में जनजीवन तथा विकास गतिविधियों को प्रभावित करती रही हैं। राज्य सरकार ने इन दोनों असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश सुनिश्चित किया है। डकैती तथा नक्सली समस्या पर पूर्ण नियंत्रण रखा गया। सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने, गंभीर अपराधों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों की बेहतरी तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये दृढ़ संकल्पित है। यह संकल्प, हम सभी की सक्रिय भागीदारी से ही पूरा होगा। आइए हम समृद्ध एवं विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में सहभागी बनें।

जय हिन्द।